अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 1 दिसंबर 2018

कूटनीति की दुनिया में कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है...

...लिंकन कैफी, *अमेरिकी राजनेता*

बेशक खेती-किसानी के मामले में पिछली सरकारों का रवैया भी संवेदनशील नहीं था, लेकिन देश के किसानों को अगर अपनी तकलीफ बताने के लिए बार-बार सड़क पर उतरना पड़े, तो यह हमारी आर्थिक नीति की विसंगतियों का ही उदाहरण है।

सड़कों पर अन्नदाता

देश के अन्नदाताओं को अपनी तकलीफें बताने के लिए बार-बार राजधानी की ओर कूच करना पड़े, तो यह हमारी आर्थिक नीतियों में व्याप्त विसंगतियों का ही सबूत है। एक साल में चौथी बार परेशान किसानों को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का काम करता है, जिन किसानों के बूते हर साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की उपलब्धि यह देश हासिल करता है, वह कृषि क्षेत्र युवाओं के खेती से होते मोहभंग, किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं और उत्तरोत्तर सरकारों की खेती-किसानी के प्रति संवेदनहीनता के कारण ही ज्यादा जाना जाता है। राजपथ पर उमड़ आए किसानों की कहानियां शोषण और संवेदनहीनता की कहानियां थीं। उनकी शिकायत थी कि बीज, कीटनाशक, उर्वरक आदि महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन अपने उत्पादों की कीमत के मामले में वे छले जाते हैं। वे संसद का विशेष सत्र बुलाकर खेती से संबंधित दो प्राइवेट मेम्बर्स बिल को पारित कराने की मांग कर रहे थे, जिन पर भाजपा को छोड़कर इक्कीस विपक्षी दलों की सहमति है-ये बिल हैं-एकमुश्त सभी किसानों की कर्ज माफी और फसलों के लाभकारी मूल्य पाने का कानूनी अधिकार। हालांकि एकमुश्त कर्ज माफी का फैसला लेना न तो आसान है और न ही व्यावहारिक, पर संवेदनशील तरीके से किसानों की समस्या का समाधान तो किया ही जा सकता है। अभी तो हाल यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का हिसाब भी सरकार तीन तरीके से करती है। इसीलिए किसानों ने एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा सुझाए गए सी 2 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग की, जिसमें उत्पादन की लागत में पचास फीसदी और जोड़ने का प्रावधान है। इस बार संतोषजनक यह रहा कि दिल्ली आए किसानों को पूर्व सैनिकों, शिक्षकों, छात्रों और डॉक्टरों की मदद मिली-उनके

खाने-पीने और चिकित्सा की व्यवस्था की गई, अन्यथा तो खाने की व्यवस्था खुद करने, उन्हें खदेड़ने और उनके ट्रैक्टर पंक्चर कर देने के ही ब्योरे ज्यादा आते हैं। हमारा समाज किसानों की तकलीफ और उनके महत्व को समझ रहा है। सरकारों को भी उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जबकि अवसरवादी राजनीति का हाल यह है कि विपक्ष में होने पर किसानों के साथ खड़ी होने वाली पार्टियों का भी खेती-किसानी के प्रति रवैया संवेदनहीन ही रहा है।

अफगानिस्तान में भारत की जगह

नई दिल्ली को एक वास्तविक सामाजिक सुलह प्रक्रिया का समर्थन करके अफगान संघर्ष को खत्म करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। मॉस्को की बैठक में भारत का अपने अनुभवी, सेवानिवृत्त राजनयिकों को भेजने का फैसला समझदारी भरा कदम था।

अविनाश पालीवाल
एसओएएस यूनिवर्सिटी, लंदन में व्याख्याता

इस तथ्य के बावजूद कि सशस्त्र समूहों ने खुद को साबित किया है और हम सबको दिखाया है कि वे कट्टर हैं, अफगान सरकार शांति चाहती है-यह कहना था मार्च, 2018 में सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैय्यद अकबरुद्दीन का। वर्ष 2015 में इसी तरह के घटनाक्रम पर भारत ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी थी, जब भारत ने गनी का झुकाव इस्लामाबाद की तरफ देखा था, अब भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 2018 की गतिविधियों को समर्थन देने का आह्वान किया है।

नई दिल्ली ने अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया क्यों की? यह सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण अफगान के आधिकारिक नेतृत्व वाली सुलह प्रक्रियाओं का समर्थन करने का रहा है। तथ्य यह है कि काबुल ने ही वर्ष 2015 और 2018 में सुलह प्रक्रियाओं का नेतृत्व किया। भारत ने हाल ही में मॉस्को द्वारा आयोजित बहुपक्षीय वार्ता में गैर आधिकारिक रूप से हिस्सा लिया, जिसमें अफगान तालिबान के प्रतिनिधि भी शामिल थे, पर गनी का एक भी विश्वस्त शामिल नहीं था। अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते अलगाव के कारण इस सवाल का जवाब ढूंढना आवश्यक है। अतीत में, खासकर 1990 के दशक के दौरान इसी तरह के अलगाव और पाकिस्तान के बढ़ते असंगत प्रभाव की भावना ने भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी गुटों के समर्थन के लिए प्रेरित किया था। भविष्य में इस सक्रियता की पुनरावृत्ति के कारण अफगान टकराव के समाधान के बजाय उसके बढ़ने की आशंका है।

काबुल के शांति प्रस्ताव पर भारत की विरोधाभासी प्रतिक्रिया का स्रोत अमेरिका की अफगान नीति पर उसकी धारणा और उसके विश्वास में निहित है। अमेरिका पर इस तरह की निर्भरता भारत की अफगान नीति को गहरे संकट में डालती है। पहला, अगर अमेरिका वार्ता में पाकिस्तान को

ज्यादा तवज्जो दे या अल्पकालीन सूचना पर अपने जवानों की मौजूदगी घटा दे, तो यह भारत के विकल्पों को सीमित करता है। दूसरा, यह दर्शाता है कि नई दिल्ली या तो अफगान संघर्ष से बहुत प्रतिरक्षित हो गई है या वास्तव में इसे खत्म करने के प्रति बहुत अनजान हो गई है। तीसरा, भारतीय नीति-निर्माताओं ने सोवियत-अफगान युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा है। अमेरिका पर भारत की अफगान नीति की निर्भरता 1980 के दशक में मॉस्को पर निर्भरता से अलग नहीं है। तब भारत युद्ध खत्म करने के प्रति सोवियत संघ की गंभीरता या उसकी संरचनात्मक समस्या को समझने में विफल रहा, भले ही पाकिस्तानी मांगों को स्वीकार करना इसकी जरूरत हो। हालांकि आज भारत ट्रंप के राष्ट्रपति काल से जुड़ी अनिश्चितता को समझता है, फिर भी अफगानिस्तान में अपने लिए जगह बनाना और अपनी अफगान नीति की वकालत करना बाकी है।

भारत की अफगान नीति का सबसे प्रमुख वाहक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक संतुलन पर प्रहार करने की उसकी इच्छा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निरंतर, संभवतः अपरिवर्तनीय और व्यापक शक्ति अंतर को देखते हुए यह एक महात्वाकांक्षी इच्छा है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के बीच सुलह शर्तों में पाकिस्तान हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अफगान युद्ध का विरोध करते हुए ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इसे खत्म करने का वायदा किया था। फिर भी फरवरी और अगस्त, 2017 के बीच उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एच. आर मैकमास्टर ने मूल रूप से भिन्न नीति लागू करने में सफलता प्राप्त की। अफगानिस्तान से समय से पहले जवानों को वापस नहीं बुलाने पर दृढ़ मैकमास्टर ने नीति समीक्षा शुरू की। उनका उद्देश्य यह जांचना था कि क्षेत्र में लंबे समय तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर क्षेत्रीय शक्तियां कैसी प्रतिक्रिया देती हैं और ऐसा करने के लिए वह प्रशासन के भीतर पर्याप्त समर्थन हासिल करना चाहते थे। इन दोनों में वह सफल रहे।

चीन के साथ अमेरिका के खराब रिश्तों, कुछ अफगान तालिबान गुटों को रूस द्वारा हथियार प्रदान करने और पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी एवं अफगान बलों की आलोचना को देखते हुए मैकमास्टर ने विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार के रूप में अपनी अफगान नीति पहल को देखने के लिए भारत को शामिल किया। अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीति में भारत की (अस्थायी रूप से) ऊंची भूमिका ट्रंप के अगस्त 2017 के भाषण में दिखी। अमेरिका की अफगान नीति में ऐसे बदलाव से पता चलता है कि भारत ने गनी के 2018 के सुलह प्रस्ताव पर क्यों सतर्क प्रतिक्रिया दी। ट्रंप के भाषण ने भविष्य की रणनीतिक स्पष्टता की पेशकश की, जिसका भारत के सत्ता गलियारों में स्वागत किया गया। बढ़ते अमेरिकी सैन्य समर्थन के वायदे ने भारत में यह विश्वास व्यक्त किया कि 2001 से गनी द्वारा शांति की कोशिशों से अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी को कोई खतरा नहीं है। इसने वह संतुलन सुनिश्चित किया, जो भारत काबुल और इस्लामाबाद के बीच चाहता है।

जुलाई में अफगान तालिबान के साथ अमेरिका की सीधी बातचीत ने भारत को फिर असमंजस की स्थिति में डाल दिया। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत मोदी सरकार ने अफगान तालिबान के साथ एक स्वतंत्र चैनल बनाने को कोई महत्व नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते भी निचले स्तर पर पहुंच गए। अगर अमेरिका ने इस नई पहल के हिस्से के रूप में अफगान तालिबान के साथ समझौता करने का फैसला किया, तो अफगानिस्तान में भारत के रणनीतिक रूप से कमजोर और राजनयिक रूप से अलग-थलग पड़ने की आशंका है।

सीमित क्षमताओं और स्थायी रणनीतिक हित वाले पड़ोसी के रूप में, भारत को यह चुनने की सुविधा नहीं है कि अफगानिस्तान में कैसे, कब, क्यों और किसके साथ जुड़ना है। पाकिस्तान के बरक्स अल्पकालीन लाभ के बारे में सोचने के बजाय नई दिल्ली को एक वास्तविक सामाजिक सुलह प्रक्रिया का समर्थन करके अफगान संघर्ष को खत्म करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए मॉस्को की बैठक में भारत का अपने अनुभवी, सेवानिवृत्त राजनयिकों को भेजने का फैसला एक समझदारी भरा कदम था।

अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट थी मेरी पढ़ाई

अपनी कहानी

>>मधुमाला चट्टोपाध्याय

मैंने अंडमान की लगभग सभी जनजातियों के बीच रहकर शोध कार्य किया है। लेकिन मैंने कभी सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया। मेरा अनुभव है कि तमाम जनजातियां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

फाइल फोटो

उस सुबह मैंने एक खबर पढ़ी कि अंडमान के एक द्वीप पर विलुप्तप्राय आदिवासी समुदाय ओंग के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ है। मैं दौड़ती हुई पिता के पास गई और बोली कि पापा, मैं अगली छुट्टियों में वहीं जाऊंगी। रेलवे में अकाउंट ऑफिसर के पद पर तैनात मेरे पिता ने तब मुझे समझाते हुए कहा था कि वहां हर कोई नहीं जा सकता है। मात्र पत्रकार या शोधार्थियों को ही वहां जाने की अनुमति है। मैं उस वक्त सिर्फ बारह साल की थी। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं शोधार्थी बनूंगी।

मानव विज्ञान चुनने का कारण

मैं मूलतः कोलकाता के उपनगर हावड़ा से हूं। जब मकसद साफ हो, तो पढ़ाई के विषय चुनने में दिक्कत नहीं होती। शुरुआती शिक्षा के बाद मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान विषय से बीएससी की। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मैंने पूछताछ की थी कि कौन-सा विषय है, जिसमें आदिवासियों के बारे में पढ़ाया जाएगा? किसी ने मुझे बताया था-मानवविज्ञान। वहां से लौटकर जब मैंने घरवालों को अपने विषय चुनाव के बारे में बताया, तो वे इससे बहुत खुश नहीं हुए। मैंने उनसे कहा, 'यह पढ़ाई ही ओंग तक पहुंचने का मेरा पासपोर्ट है।'

जब अंडमान जाने से रोका गया

जब मैंने अंडमान में जाकर शोध करने के लिए एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पीएच डी के लिए आवेदन किया, तो मुझसे कहा गया कि वहां जाना किसी महिला शोधार्थी के लिए सुरक्षित नहीं है। शानदार अकादमिक कॅरिअर के बावजूद मुझे अंडमान जाने की अनुमति देने से पहले एक शपथ पत्र पर मेरे अभिभावकों के दस्तखत कराए गए कि किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। उस दिन दस्तखत करते हुए मेरी मां के हाथ पिता के हाथों से ज्यादा स्थिर थे, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी के बचपन का सपना अधूरा रह जाए।

संपर्क और हमला

अगले कई वर्षों तक मैंने अंडमान की विभिन्न जनजातियों के बारे में शोध जारी रखा। इसी शोध के दौरान 1991 में सरकारी टीम के साथ मैंने पहली बार सेंटिनल द्वीप पर कदम रखे। वहां जाने से पहले मैंने इस जनजाति के बारे में पूरी रिसर्च की थी। उनकी भाषा और उनके व्यवहार के बारे में मुझे पहले से अंदाजा था। मेरी टीम आदिवासियों के लिए तोहफे स्वरूप नारियल ले गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। डेढ़ महीने बाद मैं वहां दोबारा गई, पर उस दफे मुझ पर हमला हुआ। हालांकि उन्हीं लोगों के बीच की एक महिला ने मुझे बचाया भी था।

जारी रखा है शोध

उस वाकये के बाद सरकार ने सेंटिनल वासियों से दोबारा संपर्क करने की कभी कोशिश नहीं की और उस द्वीप पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पर मैंने अंडमान के दूसरे द्वीपों पर रहने वाली अन्य जनजातियों के बारे में शोध जारी रखा। जारवा जनजाति के लोगों के बीच मैं काफी हद तक घुल-मिल चुकी थी। 1989 से 1996 तक मैंने अंडमान की लगभग सभी जनजातियों के बीच रहकर शोध कार्य किया है। लेकिन मैंने कभी सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया। मैं आज भी दिल्ली में एक सरकारी महकमे के साथ मिलकर काम कर रही हूं। मेरा अनुभव है कि तमाम जनजातियां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

-नूतन कुमार गुप्ता से बातचीत पर आधारित।

फैक्ट फाइल

जी 20 शिखर बैठक

>> जी-20 देश

जी 20 की अगली बैठक 2019 में जापान के ओसाका शहर में होगी।

अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जी 20 की दो दिवसीय बैठक हो रही है। जी 20 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) और अमेरिका की सरकारों और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का समूह है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक नीतियों के अंतरराष्ट्रीय समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी पहलों के क्रम में जी 20 की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत विमर्श के उद्देश्य से जी 20 की स्थापना 26 सितंबर, 1999 को बर्लिन में की गई थी। शुरुआत में यह सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक तक सीमित था। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया और जर्मन वित्त मंत्री हैंस आइशेल ने उद्घाटन बैठक की मेजबानी की थी। 2008 में इसका दायरा बढ़ाया गया और शिखर बैठक में सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने लगे। इस संगठन में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, लिहाजा इसकी शिखर बैठक में यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त रूप से जी 20 की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की कुल जीडीपी में 85 फीसदी की हिस्सेदारी करती हैं। जी 20 की अगली बैठक 2019 में ओसाका शहर में होगी।

चांद के लिए शुरू होंगी उड़ानें

नासा ने नौ अमेरिकी कंपनियों का चयन किया है, जो चांद की सतह पर पहुंचाने वाले अंतरिक्ष यान बनाएंगी।

न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए केनेथ चैंग

अंतरिक्ष यात्री शायद एक दिन फिर चांद पर पैर रखें, और छोटे रोबोटिक अंतरिक्ष यान वहां उनकी प्रतीक्षा करें। नासा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने नौ कंपनियों का चयन किया है, जो नासा के लिए छोटे पेलोड चांद की सतह पर ले जाएंगी। 'हम घरेलू स्तर पर ऐसी क्षमता निर्मित कर रहे हैं, जिससे कि चांद की सतह पर पहुंचना और वहां से लौटना संभव हो सके' नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेन्स्टाइन कहते हैं। गौरतलब है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने आखिरी बार 1972 में चांद की सतह पर कदम रखे थे। उसके बाद से नासा का कोई अंतरिक्ष यान वहां तक नहीं पहुंचा है।

ट्रंप प्रशासन चंद्र अभियान को अपनी तकनीकी प्रगति जांचने के पैमाने के तौर पर देख रहा है। साथ ही वह ऐसी रणनीतियों के बारे में भी सोच रहा है, जिससे अंतरिक्ष में जाने का खर्च कम हो। इसी के तहत नई व्यावसायिक कंपनियों को तरजीह दी जा रही है। दरअसल अंतरिक्ष अभियान के बेहद खर्चीले होने के कारण ही अमेरिका ने हाल के दशकों में इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। निजी

कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने से जहां सरकार का दबाव इस क्षेत्र में कम होगा, वहीं निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका लाभ अंततः अंतरिक्ष की यात्रा करने वालों को मिलेगा। इन कंपनियों को दस साल के लिए लगभग 2.6 अरब डॉलर का ठेका दिया जा रहा है। जल्दी ही इन उड़ानों के शुरू हो जाने की उम्मीद है। नासा के अधिकारियों के मुताबिक, एक साल में दो और दस साल में कुल बीस उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है।

नासा के इंजीनियर इन अंतरिक्ष यानों की डिजाइन तैयार नहीं कर रहे। इसके बजाय कंपनियों को ठेका देते वक्त उसने साफ-साफ बता दिया है कि अंतरिक्ष यान में किस तरह की सुविधाएं चाहिए। इस तरह नासा भी अब एक उपभोक्ता बन गया है। ये निजी अंतरिक्ष यान व्यावसायिक जरूरतें भी पूरी करेंगे। दरअसल दुनिया भर के उद्यमी पिछले कुछ वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें चांद की सतह पर खनन करने का अधिकार मिलना चाहिए। नासा की यह पहल उसी दिशा में है।

गौरतलब है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नासा को चांद के बजाय मंगल पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने मंगल के बजाय चंद्र अभियान को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों के 2020 से पहले वहां पहुंचने की उम्मीद नहीं है। नासा का यह भी मानना है कि जिन निजी कंपनियों को उन्होंने चुना है, उनमें से सभी के सफल होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इससे एक माहौल बनेगा, जिसका भविष्य में लाभ मिलेगा। ब्रिडेन्स्टाइन का यह भी कहना है कि नासा मंगल को भी अपने एजेंडे में रखेगा।

गौरतलब है कि एक इस्राइली कंपनी ने अगले साल की शुरुआत में चांद पर एक मानवरहित यान भेजने की योजना बनाई है। भारत और चीन ने भी 2019 में चांद पर मानवरहित यान भेजने की घोषणाएं की हैं।

इस हफ्ते के शब्द

सलोम जुराबिश्विली

जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। फ्रांस में जन्मी सैलोम ने इस चुनाव में 66 फीसदी वोट हासिल किए।

पफबॉल (PUFFBALL)

कनाडा की एक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में अंग्रेजी के जिन दस शब्दों को सबसे मजेदार शब्द माना गया है, उसमें यह शब्द भी शामिल है। इसका अर्थ एक प्रकार के फफूंद से है।

अर्थव्यवस्था की रफ्तार

$827 अरब

तक का हो सकता है भारतीय खुदरा खाद्यान्न बाजार 2023 तक, एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक।

सूत्र

>> कैमरॉन जॉनसन

निमंत्रण कार्ड ने दिखाई व्यावसायिक राह

व्यवसाय की शुरुआत मैंने नौ वर्ष की छोटी-सी उम्र में ही कर दी थी। सब कुछ एक मजाक की तरह शुरू हुआ। पहले मैं घर-घर जाकर सब्जियां बेचा करता था। फिर मैंने अपने पारिवारिक उत्सव के लिए निमंत्रण कार्ड बनाना शुरू किया। जिन लोगों को मैंने वह कार्ड दिया, उन्हें वे बहुत पसंद आए और जल्द ही मुझे दोस्तों व परिजनों की ओर से कार्ड बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। बस फिर क्या था, मैंने इसे अपना व्यवसाय बना लिया और पैसे कमाने लगा। कुछ ही वर्षों में व्यवसाय से प्राप्त पैसों से मैंने निर्माताओं से थोक में गुड़िया खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने खुद अपनी वेबसाइट बनाई। जब मेरे दोस्त मैदानों में खेल रहे थे, मैं इंटरनेट पर पैसे कमा रहा था। इस तरह मैंने मात्र बारह वर्ष की उम्र में पचास हजार डॉलर कमा लिया। फिर मैंने माई ईजेड मेल पर काम शुरू किया, यह एक ऐसी सेवा थी, जो प्राप्तकर्ताओं की जानकारी दिखाए बिना किसी खास अकाउंट में ईमेल फॉरवर्ड करती थी। इसे विकसित करने के लिए मैंने एक कोडर को रखा और कुछ ही वर्षों में विज्ञापन से मेरी कमाई प्रति महीने तीन हजार डॉलर हो गई।

फिर मैंने अपने दो किशोर दोस्तों के साथ सर्फिंगप्राइज डॉट कॉम नामक ऑनलाइन विज्ञापन कंपनी शुरू की। पंद्रह वर्ष की उम्र में मैं तीन से चार लाख डॉलर प्रति महीने कमाने लगा। ग्रेजुएशन से पहले मेरे पास कुल संपत्ति दस लाख डॉलर से ज्यादा थी। फिर तो सिलसिला ही चल निकला और मैं एक के बाद एक व्यवसाय में निवेश करता गया। आज मैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी मैजिक सिटी फोर्ड लिंकन का सीईओ हूं और दुनिया भर में विभिन्न उद्यमों में निवेश करता हूं। कार्ड छापने के व्यवसाय के बाद जब मैं दूसरे व्यवसायों में लग गया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि यह मेरा जुनून ही था, जिसने मेरा मार्गदर्शन किया। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच ने मुझे व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया। अगर ये संसाधन नहीं होते, तो आज मैं जहां हूं, उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। इंटरनेट किसी भी उम्र, जाति, स्थान, अनुभव, शिक्षा स्तर के उद्यमियों को एक समान मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। यह वास्तव में एक वैश्विक बाजार है। खास बात यह है कि व्यवसाय में मुझे मजा आता था और यह किसी भी उद्यमी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए जुनून और समर्पण जरूरी है।

किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए जुनून और समर्पण जरूरी है। जो काम कर रहे हैं, उसमें आनंद उठाना चाहिए।